

प्रेषक,

अनूप वधावन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी (जनपद हरिद्वार छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग देहरादून : दिनांक 09 जुलाई 2008

विषय:-उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष, 2003 में हुए थे। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इन पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष, 2008 में निर्धारित है। वैधानिक व्यवस्था के अनुसार सभी स्तरों की पंचायतों में पदों तथा स्थानों का आरक्षण संविधान एवं अधिनियमों में विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

2. सर्वप्रथम पदों एवं स्थानों के आरक्षण का निर्धारण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 D के अन्तर्गत व्यवस्था के अधीन तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 11-क, धारा 12 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 6-क, 7-क एवं धारा 18-क तथा 19-क तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) में विहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3. जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही नियमान्तर्गत शासन स्तर से यथासमय की जायेगी। प्रत्येक जिले में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों तथा खण्डवार ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के आरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। इससे पूर्व जिलावार प्रमुखों के तथा खण्डवार प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या क्रमशः शासन स्तर से तथा निदेशक पंचायतीराज द्वारा अवधारित कर सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जनपदवार प्रमुख पदों की अवधारित संख्या का विवरण संलग्न है।

4. उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों हेतु जिला पंचायतों के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख एवं ग्राम पंचायतों के प्रधान के पदों का अवधारण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 D (4) के परन्तुक के अधीन निम्नांकित सूत्र के अनुसार किया जाएगा। अवधारित होने वाले पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(क) जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु अवधारित पद:-

राज्य में सम्बन्धित जाति
की जनसंख्या

-----X कुल अध्यक्ष पदों की संख्या = राज्य में जाति विशेष हेतु आरक्षित पद
राज्य की कुल जनसंख्या (अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद 14 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत होंगे)

सूत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यक्ष पदों का आरक्षण

256129

-----X 13= .39=0

8489349

सूत्र के अनुसार अनुसूचित जाति हेतु अध्यक्ष पदों का आरक्षण

1517186

-----X 13= 2.32=2 01 महिला 01 अनारक्षित

8489349

सूत्र के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु अध्यक्ष पदों का आरक्षण

1224517

-----X 13= 1.87 (अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)

8489349

अर्थात् 01 पद = 01 महिला

(ख) प्रमुख पद हेतु अवधारित पद:-

राज्य में सम्बन्धित जाति
की जनसंख्या

-----X कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या = राज्य में जाति विशेष हेतु आरक्षित पद
राज्य की कुल जनसंख्या (अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद 14 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत होंगे)

सूत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु प्रमुख पदों का आरक्षण

256129

-----X 95= 2.86=3 02 महिला 01 अनारक्षित

8489349

सूत्र के अनुसार अनुसूचित जाति हेतु प्रमुख पदों का आरक्षण
1517186
-----X 95= 16.97=17 09 महिला 08 अनारक्षित
8489349

नोट:- राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति हेतु कुल 17 पद अवधारित होते हैं किन्तु जनपद को इकाई मानते हुए सूत्र के अनुसार वितरण करने पर कुल 20 पद वितरित हो रहे हैं, जिसमें से 10 महिलाओं को आवंटित किये जाने हैं। जिसमें 02 पद पूर्व में ही जनपद हरिद्वार को आवंटित हो चुके हैं, 02 पदों में से 01 पद महिला को आवंटित है।

सूत्र के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमुख पदों का आरक्षण
1224517
-----X 95= 13.70=14 किन्तु 14 प्रतिशत की सीमा
8489349 में रखने पर 13.3=13 07 महिला 06 अनारक्षित

नोट:- राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर 13.70 अर्थात 14 पद अवधारित हो रहे हैं, जिन्हें 14 प्रतिशत तक सीमित करते हुए 13 पद अवधारित होते हैं। सूत्र के अनुसार जनपदों में वितरण के पश्चात कुल 11 पद वितरित हो पा रहे हैं। इसलिए 02 पदों को वितरित न करने हेतु छूट प्रदान की गयी है। उक्त 11 पदों में से 03 पद पूर्व में ही जनपद हरिद्वार को आवंटित है। जिसमें से 01 पद महिला का है।

(ग) प्रधान पद हेतु अवधारित पद

सूत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु प्रधान पदों का आरक्षण
256129
-----X 7541= 227.51=228
8489349

सूत्र के अनुसार अनुसूचित जाति हेतु प्रधान पदों का आरक्षण
1517186
-----X = 7541=1347.7=1348
8489349

सूत्र के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रधान पदों का आरक्षण
1224517
-----X 7541=1087.73=1088 किन्तु 14% की सीमा के अन्तर्गत 1055.74 अर्थात 1055 पद
8489349

नोट:- निदेशक, पंचायती राज द्वारा अपने पत्र संख्या 1472 दिनांक 28-2-2008 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नियमावली के अनुसार खण्डवार 14 प्रतिशत सीमित न करते हुए खण्ड में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का खण्ड में कुल जनसंख्या से अनुपात के अनुसार वितरण



करने पर कुल 783 पद वितरित हो रहे हैं। अतः उनके द्वारा 272 पदों हेतु छूट का अनुरोध किया गया है। अतः निदेशक, पंचायतीराज के अनुरोध पर 272 पदों की छूट प्रदान की जाती है।

5. ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पदों की संख्या संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा-11 क की उप धारा-2 और 4 के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार निकाली जायेगी कि यदि शेष भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष भाजक के आधे से कम हो तो इसे छोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पदों की संख्या निर्धारित हो जायेगी। महिलाओं के लिए आरक्षित प्रधान पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए उपरोक्त नियम का पालन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या आरक्षित वर्ग की महिलाओं की संख्या को सम्मिलित करते हुए कुल प्रधान पदों की संख्या के आधे से कम नहीं होगी। श्रेणीवार आरक्षण की गणना करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं का आरक्षण कुल पदों अथवा स्थानों में किसी भी दशा में आधे से कम न हों।

6. इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निकाली गयी प्रधान पदों की संख्या ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिए खण्ड(क्षेत्र पंचायत) को इकाई माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि खण्ड में ग्राम पंचायतों के लिए अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग के प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात खण्ड में प्रधान पदों की संख्या में यथासाध्य वही होगा जो खण्ड में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का अनुपात खण्ड में कुल जनसंख्या के साथ होगा।


7. सर्वप्रथम प्रत्येक विकासखण्ड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पद निम्नलिखित सूत्र से आगणित किये जाए:-

$$\text{अनुसूचित जनजाति के प्रधान पदों की संख्या} = \frac{\text{विकास खण्ड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या}}{\text{विकास खण्ड की कुल जनसंख्या}} \times \text{विकास खण्ड में कुल ग्राम प्रधानों के पदों की संख्या}$$

आगणित प्रधान पदों की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर 3 में दी गयी प्रक्रियानुसार अवधारित पदों की संख्या में आई कमी को अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक अनुपातिक जनसंख्या वाले विकासखण्डों में पुनर्वितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पद निम्नलिखित सूत्र से आगणित किये जाए:-

$$\text{अनुसूचित जाति के प्रधान पदों की संख्या} = \frac{\text{विकास खण्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या}}{\text{विकास खण्ड की कुल जनसंख्या}} \times \text{विकास खण्ड में कुल ग्राम प्रधानों के पदों की संख्या}$$



उपरोक्तानुसार आगणित प्रधान पदों की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर 3 में दी गयी प्रक्रियानुसार अवधारित पदों की संख्या में आई कमी को अनुसूचित जाति की सर्वाधिक अनुपातिक जनसंख्या वाले विकासखण्डों में पुनर्वितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

8. इसी प्रकार प्रत्येक विकासखण्ड में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पदों का आगणन सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूले से किया जायेगा:-

$$\text{पिछड़ा वर्ग के प्रधान पदों की संख्या} = \frac{\text{विकास खण्ड में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या}}{\text{विकास खण्ड की कुल जनसंख्या}} \times \text{विकास खण्ड में कुल ग्राम प्रधानों के पदों की संख्या}$$

9. निम्नलिखित क्रम में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रधानों के पदों की संख्या उस खण्ड में भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों को पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी अर्थात् उस खण्ड की ग्राम पंचायतों में से वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार कि जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जातियों को, आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जातियों को और पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

आवंटन का क्रम निम्नवत् होगा:-

- (क) अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं
- (ख) अनुसूचित जनजातियां
- (ग) अनुसूचित जातियों की महिलाएं
- (घ) अनुसूचित जातियां
- (ङ) अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं
- (च) अन्य पिछड़ा वर्ग और
- (छ) महिलाएं

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्ग की जनसंख्या पंचायत क्षेत्र में दो से कम हो तो ऐसे पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान का पद यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं किया जायेगा।



उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायतों के प्रधानों के पदों की आधे से अन्यून ग्राम पंचायतों में प्रधानों के पद यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

उक्त के अधीन आवंटन के पश्चात् अवशेष ग्राम पंचायतों से ग्राम पंचायतों के प्रधानों के पदों को महिलाएं को इस प्रकार आवंटित किया जायेगा, कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए आधे से अन्यून पद महिलाओं हेतु आरक्षित हो जायेंगे, किन्तु इस प्रकार कि जिन ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सबसे अधिक अनुपातिक जनसंख्या हो, जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, उनको आवंटित किया जायेगा, और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार कि, जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित ग्राम पंचायतें महिलाओं को आवंटित नहीं की जायेंगी।

10. क्षेत्र पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों की संख्या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-7-क के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार निर्धारित जायेगी कि यदि शेष, भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या निर्धारित हो जायेगी।

11. इस प्रकार निकाली गयी प्रमुख पदों की संख्या क्षेत्र पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिए जिले को इकाई माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि क्षेत्र पंचायतों के लिए अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग के प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात जिले में प्रमुख पदों की संख्या में यथा साध्य वही होगा जो जिले में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या में अनुपात हो।

12. सर्वप्रथम प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों का निम्नलिखित सूत्र से आगणन किया जायेगा:-

$$\text{अनुसूचित जनजाति के प्रमुख पदों की संख्या} = \frac{\text{जनपद में अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या}} \times \text{जनपद में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या}$$

उपरोक्तानुसार आगणित प्रमुख पदों की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर-10 में दी गई प्रक्रियानुसार अवधारित पदों की संख्या में आई कमी को अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों में पुनर्वितरित कर पूर्ण किया जायेगा।



13. इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों का निम्नलिखित सूत्र से आगणित किये जायेगा:-

$$\text{अनुसूचित जाति के प्रमुख पदों की संख्या} = \frac{\text{जनपद में अनुसूचित जाति की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या}} \times \text{जनपद में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या}$$

उपरोक्तानुसार आगणित प्रमुख पदों की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर-10 में दी गई प्रक्रियानुसार अवधारित पदों की संख्या में आई कमी को अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों में पुनर्वितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

14. इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों का निम्नलिखित सूत्र से आगणित किये जायेगा:-

$$\text{पिछड़े वर्ग के प्रमुख पदों की संख्या} = \frac{\text{जनपद में पिछड़े वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या}} \times \text{जनपद में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या}$$

15. अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रमुखों के पदों की संख्या उस जिले में भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों को, पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या का पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुपात के आधार पर, अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी, अर्थात् उस जिले की क्षेत्र पंचायतों में से वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो उनको आवंटित की जायेगी और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहां तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित क्षेत्र पंचायत, अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और अनुसूचित जाति को आवंटित क्षेत्र पंचायत अनुसूचित जाति को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायत पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायतों की आधे से अन्यून क्षेत्र पंचायतें यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित की जायेगी।

उक्त के अधीन आवंटन के पश्चात् अवशेष क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख के पदों को महिलाओं को इस प्रकार आवंटित किया जायेगा कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए

आधे से अन्यून पद महिलाओं हेतु आरक्षित हो जाएं किन्तु इस प्रकार कि जिन क्षेत्र पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सबसे अधिक अनुपातिक जनसंख्या हो, जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, उनको आवंटित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार कि जहां तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित क्षेत्र पंचायतें महिलाओं को आवंटित नहीं की जायेगी।

16. उक्त में यथा उपबन्धित अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए जिला पंचायतों में अध्यक्षों की संख्या राज्य में भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों को पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी, अर्थात् राज्य में जिला पंचायतों में से वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो उनको आवंटित की जायेगी और वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो उनको आवंटित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहां तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पंचायत अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

उक्त के अधीन अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतों की आधे से अन्यून जिला पंचायतें यथा स्थिति, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित की जायेगी।

उक्त के अधीन आवंटन के पश्चात अवशेष जिला पंचायतों में से जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों को महिलाओं को इस प्रकार आवंटित किया जायेगा कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए आधे से अन्यून पद महिलाओं हेतु आरक्षित हो जाएं, किन्तु इस प्रकार कि जिन जिला पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्र में सबसे अधिक अनुपातिक जनसंख्या हों, जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, वे उनको आवंटित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहां तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित जिला पंचायतें महिलाओं को आवंटित नहीं की जायेगी।

17. ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 12 की उपधारा 5 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 6-क तथा 18-क के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार निकाली जायेगी जिस प्रकार उपरोक्त बिन्दु संख्या-3 में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या निर्धारित हो जायेगी।



18. यदि किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों की या अनुसूचित जातियों की या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में यथा स्थिति, अनुसूचित जनजातियों के या अनुसूचित जातियों के या पिछड़े वर्गों के परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम अवधारित किया जा सकता है।

19. यदि किसी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर कोई स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है तो उपरोक्त बिन्दु संख्या 9 में उल्लिखित क्रम का पालन इस प्रकार किया जायेगा मानों इसमें, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का या अनुसूचित जातियों का या पिछड़े वर्गों का कोई निर्देश नहीं था।

20. विभिन्न पंचायतों में स्थानों के आरक्षण सम्बन्धी उदाहरण— ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण हेतु जनपद स्तर पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी:—

उदाहरण स्वरूप किसी ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 2255 है तथा कुल परिवारों की संख्या 451 है। इस ग्राम पंचायत में कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 11 होगी और ग्राम पंचायत क्षेत्र की आबादी यथासाध्य बराबर-बराबर 11 प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, पिछड़े वर्गों की जनसंख्या निश्चित नहीं की जा सकती हैं। वही उत्तराखण्ड पंचायतीराज स्थानों व पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली के नियम-4 के अनुसार आरक्षित श्रेणी के परिवारों (श्रेणीवार) के आधार पर व्यवस्थित कर ली जायेगी अलग-अलग श्रेणियों के लिये स्थानों का निर्धारण हेतु निम्न फार्मूला है:—

सम्बन्धित आरक्षित जाति की
जनसंख्या

$$\frac{\text{पंचायत की कुल जनसंख्या}}{\text{प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या}} = \text{पंचायत में आरक्षित स्थानों की संख्या}$$

इस प्रकार निकाले जाने पर पंचायत की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े के स्थान आरक्षित होंगे तथा प्रत्येक श्रेणी में आधे से अन्यून स्थान उस श्रेणी की महिला के लिये आरक्षित होंगे। जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए चार पद आरक्षित होते हैं तो दो स्थान अनुसूचित जनजाति की महिला के लिये आरक्षित होंगे। यही प्रक्रिया अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों के आरक्षण हेतु भी अपनाई जायेगी, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में जो पद/स्थान जिस जाति के लिये आरक्षित थे वे उस जाति के लिये यथा सम्भव आरक्षित नहीं किये जायेंगे जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिला हेतु जो स्थान वर्ष, 2003 के सामान्य निर्वाचन में आरक्षित किया गया था वह स्थान वर्ष 2008 के सामान्य निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिला हेतु यथा सम्भव आरक्षित नहीं होगा। यही प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में लागू होगी।

21. उपरोक्तानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में स्थानों और प्रधान, प्रमुख पदों तथा सदस्यों के आरक्षण का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में सूचना पट पर लगाकर प्रदर्शित किया जायेगा। तथा निम्न समय सारणी के अनुसार आपत्तियाँ प्राप्त कर तथा उसका निस्तारण कर आरक्षण के अन्तिम प्रस्ताव पंचातीराज निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- | | |
|--|--------------|
| (1) अन्तिम प्रस्ताव का प्रकाशन | 12-7-2008 |
| (2) आपत्तियों प्राप्त करना | 19-7-2008 तक |
| (3) जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण | 20/21-7-2008 |
| (4) अन्तिम प्रकाशन | 21-7-2008 |
| (5) आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को प्राप्त कराने की तिथि | 22-7-2008 |
| (6) निदेशालय द्वारा शासन तथा राज्य निर्वाचन आयोग को
आरक्षण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना | 23-7-2008 |

22. कोई व्यक्ति जिसे किसी प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति हो (चाहे पूर्व में उसकी कोई आपत्ति हो अथवा नहीं) प्रस्तावों के प्रदर्शन की उक्त अवधि में प्रस्तावित आरक्षण के विरुद्ध आपत्तियां खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। प्रदर्शन की अवधि की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्र कर प्रत्येक आपत्ति का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारण उसी तिथि को किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि आपत्तिकर्ता को मौखिक सुनवाई का अवसर, जब तक वह आवश्यक न समझे, प्रदान करें और आरक्षित स्थानों और पदों को अंतिम रूप देते हुए आरक्षित स्थानों और पदों की सूची का जनसाधारण की सूचना हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के सूचना पट पर प्रकाशन किया जायेगा और सूचना प्रपत्र-1, 2, 3 तथा 4 पर प्रत्येक दशा में दिनांक 22-7-2008 तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

कृपया उक्तानुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्न- यथोपरि।



भवदीय
(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या /XII/08/86(27)/2007 तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार छोड़कर)।
8. गार्ड फाईल।

१. NIC उत्तराखण्ड देहरादून।

01/

आज्ञा से,


(एम०सी०/उप्रेती)
अपर सचिव। १/७/०८

नोट:- जनपद हरिद्वार में वर्ष 2005 में सामान्य निर्वाचन हुये थे, तत्समय में प्रचलित विधि के अनुसार एक तिहाई पद महिलाओं के लिये आरक्षण का अवधारण आधे से अन्यून के आधार पर किया गया है। अतः जनपद हरिद्वार में यह व्यवस्था आगामी सामान्य निर्वाचन (वर्ष 2010) में लागू होगी। राज्य स्तर पर महिलाओं के लिये कुल आरक्षण आधे से अन्यून के आधार पर है।

2